

# दीपम ने मुद्राकरण वाली संपत्तियों की सूची मांगी

निकुंज ओहरी  
नई दिल्ली, 8 मार्च

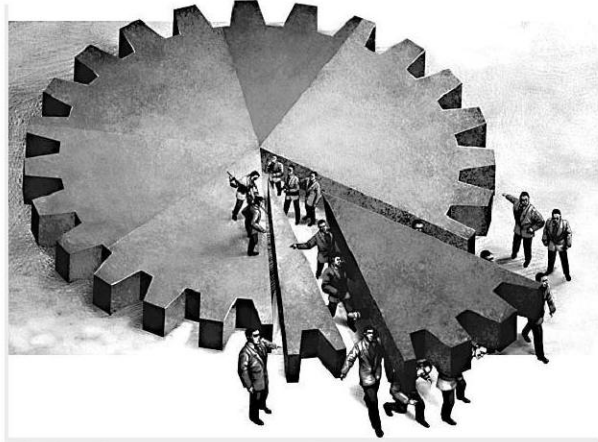
सरकार ने नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है और क्रिसिल से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों की संपत्तियों के मुद्राकरण का खाका तैयार करने को कहा है। उधर निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सरकारी कंपनियों से उन संपत्तियों की सूची मांगी है, जिन्हें बेचकर धन जुटाया जा सकता है। इस सूची का इस्तेमाल एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड तैयार करने के लिए किया जाएगा, जो इस तरह की संपत्तियों पर नजर रखेगा।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तैयार करने की कवायद कुछ उसी तरह की होगी, जैसा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 111 लाख करोड़ रुपये निवेश करने के लिए सूची

बनाई गई है।

क्रिसिल लिमिटेड की इकाई क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी को संपत्तियों के मुद्राकरण के लिए पाइपलाइन तैयार करने का काम सौंपा गया है। रेटिंग एजेंसी की इकाई ने एनआईपी का भी खाका तैयार किया था, जिसके तहत 2024-25 तक विभिन्न बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में निवेश करना था। सरकारी अधिकारी ने कहा कि पीएसयू की प्रमुख संपत्तियों की पहचान की जाएगी और पाइपलाइन के माध्यम से उनके मुद्राकरण का खाका तैयार किया जाएगा। इस पाइपलाइन में मंत्रालयों व सरकार के विभागों की संपत्तियां भी रहने की उम्मीद है, जिनका मुद्राकरण किया जा सकता है। क्रिसिल ने बिजनेस स्टैंडर्ड की ओर से मांगी गई जानकारी देने से इनकार किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था, 'चल रही सार्वजनिक बुनियादी ढांचा संपत्तियों का मुद्राकरण नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के



## बिकेगी तमाम सरकारी संपत्तियां

- दीपम ने सरकारी कंपनियों, मंत्रालयों व विभागों से उन संपत्तियों की सूची मांगी है, जिनके मुद्राकरण से धन जुटाया जा सकता है
- क्रिसिल तैयार कर रहा है सरकार के लिए नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
- इस योजना को लेकर वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वेबिनार आज

लिए बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है। पुरानी बुनियादी ढांचा संपत्तियों की एक नैशनल मोनेटाइजेशन

पाइपलाइन शुरू की जाएगी। एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जो इसमें हो रही

प्रगति पर नजर रखेगा और निवेशकों के लिए संभावनाएं प्रदान करेगा।'

अधिकारी ने कहा कि एक बार जब सरकारी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दीपम को संपत्तियों की सूची भेज देंगे, विनिवेश विभाग संपत्तियों का चयन करेगा, जिसे एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड पर डाला जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कहा था कि सरकार ने तेल और गैस, बंदरगाहों, हवाईअड्डों, बिजली क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 100 संपत्तियों को बेचने का लक्ष्य रखा है, जिससे 2.5 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को एक वेबिनार की अध्यक्षता भी करने वाली हैं, जिसमें सरकारी कंपनियों व विभागों की प्रमुख और गैर प्रमुख संपत्तियों की प्रस्तुति दीपम और नीति आयोग करेंगे। इसमें संपत्तियों के मुद्राकरण के खाके

पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही इस तरह की संपत्तियों के मुद्राकरण के कुछ मॉडलों पर भी चर्चा होगी।

केंद्रीय बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (पीजीसीआईएल) द्वारा प्रायोजित एक एक इनवित होंगे। सरकार डेडीकेटेड फ्रंट कारिडोर की संपत्तियों का भी मुद्राकरण करेगी और अगले चरण में हवाईअड्डों के परिचालन और रखरखाव को भी शामिल किया जाएगा। एनएचएआआई की परिचालन वाली टोल की सड़कें, पीजीसीआईएल की पारेषण संपत्तियां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और गेल इंडिया की तेल व गैस पाइपलाइन के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम का मुद्राकरण भी होना है। खेल मंत्रालय को स्पोर्ट्स स्टेडियमों को चिह्नित करने व उनके मुद्राकरण का काम सौंपा गया है।